THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Mr. Chairman, Sir, as you very rightly pointed out, the Chair permitted Shri Saugata Roy to make a statement under Rule 377. It is not incumbent on the Government when a statement is made under Rule 377 to make any explanation or to give any answer because all that is intended under Rule 377 is to draw the attention of the Government to a certain matter. Therefore, as far as Government is concerned, Government does not want to make any statement on this reference at this time.

14.47 hrs.

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN: The House would now resume further consideration of the following motion moved by Shri Ravindra Varma on the 5th December, 1977, namely:

"That the Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be taken into consideration".

श्री बृज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री वर्मा जी का स्वागत करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह विधेयक सदन के समक्ष रखा। मैं कल कांग्रेस के अपने साथियों की बातों को और उन के तर्कों को सुन रहा था। एक ही मित्र बोले और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जनता सरकार ने इस विधेयक को ला कर के बोनस देने की बात कही है उसमें उनकी कोई मूल बात नहीं है बल्कि कांग्रेस सरकार ने 8.33 के बोनस के सिद्धांत को स्वीकारा था। परन्तु मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी के दौरान और जितनी भी ज्यादतियां हुई और काले कानून तमाम पास किए गए उस में जिस तरीके से श्रम विरोधी कानून पास करके मजदूरों को जो बोनस पाने का हक मिला हुआ था उसको छीन लिया उसके द्वारा उस सरकार ने अपना चरित्र जनता के सामने पेश कर दिया। उसमें जो सबसे ज्यादा मजदूरों के हक या उनकी भलाई की बात करने वाले सी पी आई के साथी हैं उन्होंने बराबर श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही का समर्थन किया और उन्हीं के समर्थन का नतीजा यह हुआ कि उस समय की सरकार को इतनी ताकत मिली जिसका इस्तेमाल मजदूरों के खिलाफ करके जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, जो बड़े बड़े कारखानेदार थे उनके हितों का समर्थन किया या उनके हितों का पोषण किया। आज उसमें से बहुत से लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कभी तो वे रेल मजदूरों के बारे में और कभी जो और सरकारी मोहकमे के लोग हैं उनके बारे में बोनस के सवाल को लेकर जनता के बीच में या मजदूरों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि यह सरकार बोनस नहीं दे रही है।

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सब को दे दो। खजाना खाली कर दो।

श्री बृज भूषण तिवारी : पिछले 8–10 वर्षों में और खास तौर पर पिछले 18 महीनों में जिस बेरहमी से आपने खजाना लुटाया है, उसके हिसाब से तो हम इस हैसियत में नहीं थे कि बोनस देते। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बोनस को देकर 140 करोड़ रुपये का बोझा अपने ऊपर लिया है। यह धन का सवाल नहीं है, पैसे का सवाल नहीं है, यह हमारी आस्था का सवाल है। सर्वहारा के प्रति, मेहनत कश लोगों के प्रति, हमारी कितनी मुहब्बत है, उन के हकों के लिये हम कितना लड़ते हैं—यह उसका सबूत है। उन्हीं को साथ लेकर हमने उस तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और आप को उस गद्दी से उतार कर इस हैसियत में बैठा दिया। इस लिये हमारा यह कर्त्तव्य था कि हम उनकी

[श्री बृज भूषण तिवारी]

इस जायज मांग को पूरा करते। सभापति महोदय, हर दृष्टि से यह कानून, यह विधेयक, स्वागत योग्य है और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि बिना किसी वाद-विवाद के वे इसको पास करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें।

मान्यवर, यह सही है कि जनता पार्टी की सरकार ने एक भूतलिंगम कमेटी बैठाई है और हम यह मानते हैं कि अपने देश में जब तक राष्ट्रीय स्तर पर वेतन के बारे में, दामों के बारे में और इसके साथ-साथ मुनाफ़े के बारे में कोई नीति न हो, उस के बटवारे की कोई नीति न हो, तब तक हम कोई भी समस्या बोनस के जरिये हल नहीं कर पायगे, क्योंकि बोनस की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे कई साथी इस बात को कहेंगे और यही तर्क उस ज़माने में भी लोगों ने दिया और आज भी बहुत से लोग इसी तर्क को देते हैं कि आपने इण्डस्ट्रीयल वर्कर्स को बोनस दे दिया, मगर जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं, गवर्नमेंट अण्डर-टेकिंग्ज हैं, उनके लोगों को बोनस क्यों नहीं दिया? ......

श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी (दुर्गापुर): रेल्वे वर्कर्स के बारे में भी बोलिये।

श्री बृज भूषण तिवारी: मैं यह अर्ज करना चाहता हूं – यह ठीक है कि जो लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको बोनस मिलना चाहिये, लेकिन इस के साथ-साथ हमारे देश में वेतन के बारे में एक इन्टीग्रेटेड पालिसी की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसकी घोषणा की है, और घोषणा ही नहीं की, बल्कि बाकायदा एक कमेटी भी बना दी, उस की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। इस संदर्भ में इस विधेयक में जो बातें कही गई हैं, वे बहुत ही अच्छी बातें हैं। इसके खिलाफ़ जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं—जैसे नवल टाटा और दूसरे बड़े-बड़े पूंजीपति —उन्होंने कहा है कि इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि यह तमाम ऐसे कारखानों पर भी लागू हो गया है जो सिक पड़े हुए हैं, घाटे में चल रहे हैं। हमारी सरकार ने यह कहा है कि यदि इस प्रकार की ढील उन को दी जाती है तो फिर कोई भी कारखाना इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हमारा कारखाना मुनाफ़े में चल रहा है। मान्यवर, जो संशोधन कांग्रेस की सरकार की तरफ से एमर्जेंसी के दौरान लाया गया, उसमें प्रोडक्टिविटी की बात कही गई थी, मुनाफ़े की बात कही गई थी, बोनस को मुनाफे से लिंक किया गया था और उस कानून में जो संरक्षण पहले दिया गया था कि मिनिमम बोनस मजदूरों को देना होगा—उस अधिकार को छीन लिया गया। लेकिन हमारी तरफ़ से ऐसी सिक-मिलों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि हम अपनी इण्डस्ट्रीज को ज्यादा प्राडक्टिव बना सकें। इस तरह के तमाम प्रावधान किये गये हैं, तमाम नीतियों की घोषणायें की गई हैं, परन्तु इस के साथ-साथ जो हमारा मजदूर-वर्ग है, उस के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि ऐसा प्रावधान किया जाय। इसीलिये यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया। इस विधेयक के लाने से जो अधिकार उन को पहले प्राप्त था, उस के कानून का संरक्षण मिला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करेगा।

SHRI SAUGATA ROY (Barackpore): Sir, I rise to support the Bill which has been brought forward by Shri Ravindra Verma. Shri Verma deserves all congratulations from everybody connected with the workers for th right of bonus to the workers. I know that his task was particularly difficult because of the opposition he faced from within his own party.

I may mention that this bonus was repealed during the emergency and this is one of the things that stood against the erstwhile Congress Government. We all felt that when we went to the people during elections. A tremendous resentment had built up in the minds of the workers or their being deprived of the right to bonus which they took as their defered wage and not as a share of the profit that was made by the management.

I do not know whether it is because of Shri Verma's own wishes or because of the pressure he is facing that this very good gift to the workers was given by the left hand.

If we go through the Bill we find that this present amendment that has been brought forward by the Government restores only the minimum bonus of 8.33 per cent for the year 1976. There is no mention about how bonus will be paid in the succeeding years. There is a lurking fear in the minds of the workmen that Government in order to fulfil its election pledges has restored bonus this year which they may take back again from the workers when the time permits.

Mention has already been made in this House about the demands of the Railway employees. Some of Shri Verma's colleagues in the cabinet were erstwhile trade union leaders of the Railways. When they went on strike demanding minimum bonus for them neither Shri Verma. nor the Railway Minister nor any of the Ministers of the Government came out to say how they were going to pay bonus to the Rilawy employees who constituted single largest body of employees in this country. There are Ordnance factory employees, P & T employees, Defence employees and industrial Workers. We press this demand that along with the restoration of bonus to the workmen, bonus should be paid to Railway, Ordnance, P & T & Defence employees too.

Clause 3 prompted to have negotiated settlement.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Railway employees are holding a demonstration for bonus before the Parliament House just now. You should also mention that demonstration.

SHRI SAUGATA ROY: Just now Shrimati Parvathi Krishnan referred to the Railway Speakers demonstration in front of the Parliament House. I had an occasion to raise that issue on 30th—about the demonstration which was brought before Parliament on the 29th of November demanding the right of bonus.

I may mention again, the Government by this Act, has taken away Clause 34(3)—the right which the workers had for a negotiated settlement—in regard to the excess of the allocable surplus as allowed by this Act. This has deprived the workers in companies which have made huge profits, which have made substantial profits from getting special privileges for working in this Company and to get a due share in the profits of the company.

It may also be mentioned that the INTUC has for a long time been demanding that workers be given access to the Accounts of the management because it is very well known in this country that it is possible for a Management to manipulate accounts, to manoeuvre accounts, to manipulate balance sheet in such a way that they will show no allocable surplus. What further help has the Government given in this regard when in the calculation of the allocable surplus for bonus they have also decided to deduct the investment allowances? This will only give an upper hand to the industrialists who are out to deprive the workers of their bonus.

[Shri Saugata Roy]

15 hrs.

In this context, I will refer to the demand for bonus by the L.I.C. and G.I.C. employees. As regards the L.I.C. employees, the Government have said that it is *sub judice.*

As regards the G.I.C. employees, they have not been given bonus uptill now and the management have not yet come out with any declaration as to how they are going to give bonus to the G.I.C. employees.

I think that there are certain defects in the Bonus Act as amended.

MR. CHAIRMAN: Mr. Saugata Roy, why don't you continue your speech tomorrow?

SHRI SAUGATA ROY: Yes, Sir.

15.01 hrs.

MOTIONS *RE*. RECENT CYCLONES AND FLOODS IN THE SOUTHERN STATES

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up the motion of Shri Chitta Basu.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission, I move:

> "That this House expresses its concern at the situation arising out of the devastation caused by the recent cyclones and floods in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry and urges upon the Government to make all out efforts for undertaking a massive relief and rehabilitation programme".

Sir, while moving this motion, I would request the House to understand the grim situation on which we are called upon to deliberate. We are now called upon to discuss a grim tragedy which has befallen us recently. It is not only an important issue for the House but this is an issue of national character. I would, therefore, urge upon the Members of this House to take part in the discussion of this motion cutting across the party barriers and party affiliations and also in isolation forgetting our regional attachments.

As you know, this House—Lok Sabha—true to its tradition, expressed its deep sense of grief and agony and sorrow at the loss of lives and properties in Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala, Pondicherry and Laksha Dweep and, in a Resolution formally adopted by this House, has already expressed or conveyed the deep sense of sympathy to the members of the berieved family. We also stood in silence for a few minutes in this House itself.

As you all know, the President of the country took the earliest possible opportunity to express his sense of grief and agony at the heavy casualties and colossal loss of lives and properties and undertook a tour in the affected areas. You would also know that the Prime Minister of this country has, rightly, pointed out that the devastation was a national calamity and he was all the more explicit when he said that Andhra Pradesh and Tamil Nadu's sorrows were the sorrows of the nation and hastened to assure the entire nation to see that the Government would do whatever is required to be done. All these things, I suppose, will set the conduit of the perspective and that perspective, I hope, is the perspective of the national interest. Within this well-defined conduit of the perspective let us now proceed to discuss this tragedy which has befallen us and evaluate the troubles ahead. Unless we do our duty in this national perspective—let me say—we shall be failing in discharging our national obligation and responsibility.

My first point is to make an attempt to identify the immensity of the problem that faces us today. The losses